लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 1-15 मार्च 2022 www.haryanasamvad.gov.in अंक -37

"ऐसी वाणी बोलिये, मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आपहुं शीतल होए।"
: कबीर दास

हरियाणा में निवेश करेगा संयुक्त अरब अमीरात 2

सशक्त महिलाएं, समृद्ध समाज 6

सात नदियों का पवित्र जलस्रोतः सतकुंभा 8

7 मार्च को पेश होगा 'मनोहर' बजट

हरियाणा का वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट इस बार 7 मार्च को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। वित्तमंत्री भी होने के नाते मुख्यमंत्री स्वयं बजट प्रस्तुत करेंगे। मगर विचित्र बात यह है कि बजट की प्रस्तुति के बाद निरंतर छह दिन अवकाश रहेगा, यद्यपि बजट पर चार दिन बहस भी होगी।

अब तक के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बजट-सत्र की नौ दिन तक बैठकें होंगी और 12 दिन अवकाश में खर्च होंगे। सत्र के पहले दिन अर्थात् 2 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और 3 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा, 4 मार्च को चर्चा व धन्यवाद प्रस्ताव, 5-6 मार्च को छुट्टी रहेगी। 7 मार्च को बजट पेश, 8 से 13 मार्च तक छुट्टी, 14 से 16 मार्च तक बजट पर चर्चा, 17 से 20 मार्च तक छुट्टी, 21 मार्च को वित्त मंत्री के जवाब, 22 माच्र को विधायी कार्य होंगे।

बैठकें बढ़ाने का पावर बिजनेस एडवाइजर कमेटी के पास होता है। बिजनेस एडवाजरी कमेटी चाहे तो दो बैठकें बढ़ा सकती है। बजट सत्र का शेड्यूल निर्धारित होने के बाद सभी विभागों के पास प्रश्न भेज दिए गए हैं जिनके जवाब सरकार अब तैयार करवा रही है। वहीं बजट को लेकर प्री-बजट-चर्चा पूरी हो चुकी है। पिछली बार शीतकालीन सत्र में विपक्ष की मांग पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने दो दिन सत्र आगे बढ़ाया था।

समाज को आलोकित करते साहित्यकार

डा. चंद्र त्रिखा

हरियाणा सरकार साहित्य सृजन को बढ़ावा दे रही है। साहित्य अकादमियों द्वारा पुस्तकों के प्रकाशन के लिए अनुदान दिया जाता है। साहित्यकारों को हर वर्ष पुरस्कार दिए जाते हैं तथा उनके द्वारा रचित अच्छी रचनाओं को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाता है।

टैगोर थियेटर में आयोजित हरियाणा साहित्य पर्व के अवसर पर संस्कृत, हिंदी, पंजाबी व उर्दू भाषा के 138 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान हरियाणा संस्कृत अकादमी, हरियाणा ग्रंथ अकादमी, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी व हरियाणा उर्दू अकादमी के अंतर्गत दिए गए। अकादमियों के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने साहित्यकारों को आह्वान किया कि साहित्य की लौ धीमी नहीं होनी चाहिए। ज्ञान, शब्दकोष, रचनाओं से समाज में जनजागरण करें और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा साहित्यकारों की भूमि रही है, यहां बाबू बालमुकंद गुप्त, हाली पानीपती, दादा लख्मीचंद और बाबा फरीद जैसे साहित्यकार जन्में हैं। इन साहित्यकारों की जन्मभूमि पर साहित्य की दृष्टि से काम करने की जरुरत है। इसी कड़ी में बाबू बालमुकंद गुप्त के पैतृक गांव रेवाड़ी के गुड़ियानी में उनकी हवेली पर एक सरकारी ई-लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इससे युवाओं को साहित्य पढ़ने का मौका मिलेगा।

> मुख्यमंत्री का भाषण लीक से हटकर था। उन्होंने जहां एक ओर सस्वर कविता पाठ किया वहीं संस्कृत के कुछ श्लोक भी सस्वर पढ़े। उन्होंने हर सम्मानित साहित्यकार से निजी संवाद भी स्थापित किया।

एक समान फॉर्मूले से दी जाए सम्मान राशि

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सभी भाषाओं के साहित्यकार समान होते हैं, ऐसे में सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कार राशि भी समान होनी चाहिए। हरियाणा की साहित्य अकादमियों को पुरस्कार राशि को लेकर एक समान फॉर्मूला बनाया जाए। अभी तक हरियाणा की चारों साहित्य अकादमियां साहित्य के क्षेत्र में अलग-अलग पुरस्कार राशि दे रही हैं।

साहित्यकार होना अपने आप में सम्मान

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साहित्यकार होना अपने आप में सम्मान है। उन्होंने कहा कि साहित्यकार और साहित्य देश व समाज की सीमाओं में नहीं बंधे होते। वे कहीं भी अपने साहित्य से समाज को जागरूक कर सकते हैं। साहित्य में कही गई बात कई बार लोगों का पूरा जीवन सुधार देती है। संतों की वाणी सुनकर बुराई से ग्रसित लोगों के जीवन में भी बदलाव आ जाता है।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने कहा कि राज्य की सभी अकादमी उत्कृष्ट काम कर रही हैं । उन्होंने कहा कि साहित्यकारों के प्रति मुख्यमंत्री का अगाध प्रेम है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा साहित्य पर्व के सफल आयोजन पर डॉ. अमित अग्रवाल व हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष डॉ. चंद्र त्रिखा को बधाई दी।

ये साहित्यकार हुए सम्मानित

आजीवन साहित्य साधना सम्मान वर्ष 2017 के लिए डॉ. कमल कशोर गोयनका व वर्ष 2018 के लिए डॉ. सुरेश गौतम, 2019 के लिए श्री माधव कौशिक और 2020 के लिए श्री ज्ञानप्रकाश विवेक को 7-7 लाख रुपए की पुरस्कार राशि व प्रशस्ति पत्र दिया गया। फखे हरियाणा सम्मान वर्ष 2019 के लिए डॉ. हिम्मत सिंह सिन्हां नाजिम, वर्ष 2020 के लिए डॉ. कुमार पानीपती को 5-5 लाख रुपए की राशि व प्रशस्ति पत्र दिया गया। इसी प्रकार महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान वर्ष 2017 के लिए डॉ. पूर्ण चंद शर्मा, 2018 के लिए श्री मधुकांत, डॉ. संतराम देशवाल, वर्ष 2019 के लिए डॉ. सुदर्शन रत्नाकर व श्रीमति चंद्रकांता, वर्ष 2020 के लिए डॉ. सुभाष रस्तोगी को 5-5 लाख रुपए की राशि व प्रशस्ति पत्र दिए गए। इसके अलावा अलग-अलग श्रेणियों में कुल 138 साहित्यकार सम्मानित हुए।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

यूक्रेन मामलों में सहायता नंबर

यूक्रेन में मौजूदा तनाव को देखते हुए वहां फंसे प्रदेश के नागरिकों के परिजनों की सुविधा के लिए कुछ फोन नंबर जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने स्थिति की निगरानी और नियंत्रण के संबंध में बताया कि भारत सरकार ने पहले ही विदेश मंत्रालय के तहत विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। दिल्ली में स्थापित नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर (+91 11 23012113), (+91 11 23014104),(+91 11 23017905) और टोल फ्री नंबर 1800118797 है। ईमेलः- situationroom@mea.gov.in है।

यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास में हैल्पलाईन फोन नंबर (+380 997300428) तथा (+380 997300483) है और ईमेलः- consv.kyiv@mea.gov.in हैं। इसी तरह का नियंत्रण कक्ष हरियाणा में विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से स्थापित किया गया है। (+91 9212314595 (व्हाट्सएप) और ईमेल contactusatfcd@gmail.com पर प्रश्नों और शिकायतों को लिया जाएगा।

आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ा

हरियाणा सरकार ने 'आयुष्मान भारत'का लाभ उन सभी परिवारों को देने का फैसला किया है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है और जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों में शामिल नहीं हैं। ऐसे सभी सत्यापित आय वाले परिवारों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सत्यापित परिवारों का डेटा आयुष्मान भारत पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ताकि वे अपने कार्ड प्राप्त कर सकें।

किसानों को भेजी फसल मुआवजा राशि

हरियाणा सरकार ने खरीफ-2021 के दौरान राज्य में भारी वर्षा, जलभराव तथा कीट हमलों से हुए फसलों के नुकसान की एवज में 866 गांवों के 8,95,712 किसानों को 561.11 करोड़ रुपए मुआवजा राशि सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित करने की शुरुआत की है।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने जिला उपायुक्तों को रबी- 2022 के दौरान फसलों को हुए नुकसान के आकलन के लिए वर्तमान में चल रही गिरदावरी को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को मुआवजा राशि समय पर मिल सके।

संपादकीय

लोकसाहित्यकारों को विशेष अधिमान

साहित्यकार और साहित्य देश व समाज की सीमाओं में नहीं बंधे होते। वे कहीं भी अपने साहित्य से समाज को जागरूक कर सकते हैं। साहित्य में कही गई बात कई बार लोगों का पूरा जीवन सुधार देती है। संतों की वाणी सुनकर बुराई से ग्रसित लोगों के जीवन में भी बदलाव आ जाता है।

इंटरनेट के दौर में युवाओं की साहित्य के प्रति रूचि कम हो रही है, उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। साहित्य अकादमियों के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। साहित्य के क्षेत्र में योगदान कम न हो इसलिए सभी साहित्य अकादमियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने सम्मान समारोह में साहित्यकारों को आह्वान किया कि साहित्य की लौ धीमी नहीं होनी चाहिए। ज्ञान, शब्दकोष, रचनाओं से समाज में जनजागरण करें और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएं।

हरियाणा साहित्य अकादमी ने लोकसाहित्य व लोकसंस्कृति को विशेष बढ़ावा देने के लिए इस बार साहित्य पर्व 2022 में 17 साहित्यकारों को हरियाणवी भाषा एवं लोकसंस्कृति व हरियाणवी सृजनशीलता के क्षेत्र में सम्मानित किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं अकादमी अध्यक्ष द्वारा सम्मानित 43 हिंदी-हरियाणवी कृतिकारों में से जिन 17 को इस वर्ग में सम्मानित किया गया है, उनमें हरियाणवी भाषा, संस्कृति एवं लोक साहित्य के संदर्भ में सृजनात्मक लेखन तथा शोध कार्य करने वाले सम्मानित साहित्यकार इस प्रकार है- डॉ. पूर्णचन्द शर्मा (महाकवि सूरदास सम्मान); डॉ. रामपत्त चहल, आचार्य महावीर प्रसाद शास्त्री, श्री हरिकृष्ण द्विवेदी (पं. माधवप्रसाद मिश्र सम्मान); श्री सुरेश जांगिड़ (लाला देशबंधु गुप्त सम्मान); श्री रामपत्त गौड़ (पं. लखमीचंद सम्मान); डॉ. महासिंह पूनिया, श्री सत्यवीर नाहड़िया, डॉ. बालकिशन शर्मा, श्रीमती सरोज दहिया (जनकवि मेहर सिंह सम्मान); डॉ. राजेन्द्र बड़गूजर (हरियाणा लोक साहित्य साधना सम्मान); श्री मनजीत सिंह, श्री महेन्द्र शर्मा, डॉ. अशोक बत्रा (आदित्य-अल्हड़ हास्य सम्मान); डॉ. शमीम शर्मा, श्रीमती कमलेश चौधरी, डॉ. ज्ञानी देवी (श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान) शामिल हैं। अकादमी ने भविष्य में युवा-लेखन को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए भी विशेष कार्य योजना तैयार की गई है।

- डा चंद्र त्रिखा

आंगनवाड़ी वर्करों को सबसे अधिक मानदेय

हरियाणा में कार्यरत आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों को उत्तर भारत के राज्यों में सर्वाधिक व देशभर में दूसरे स्थान पर मानदेय एवं अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। राज्य द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने हिस्से के मानदेय में सर्वाधिक 9961 रुपए का मासिक योगदान दिया जा रहा है जबकि इसमें केंद्र का हिस्सा 2700 रुपए है।

हरियाणा में वर्ष 2014 में आंगनवाड़ी वर्कर को 7500 रुपए और आंगनवाड़ी हेल्पर को 3500 रुपए बतौर मानदेय मिलता था जो कि अब लगभग दोगुना हो चुका है। हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रति माह कुल 12661 रुपए, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर को 11401 रुपए व सहायिका को 6781 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। अन्य राज्यों में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों को दिए जाने वाले मानदेय की तुलनात्मक जानकारी यह है कि तमिलनाडु में आंगनवाड़ी वर्कर को मात्र 12,200 रुपए, छत्तीसगढ़ में 6500 रुपए, मध्यप्रदेश में 10 हजार रुपए, पश्चिम बंगाल में 8250 और पंजाब में 9500 रुपए मानदेय दिया जा रहा है जो कि हरियाणा से काफी कम है। इसी तरह मिनी आंगनवाड़ी वर्कर को जहां हरियाणा में 11401 रुपए मानदेय दिया जा रहा है वहीं तमिलनाडु में 9400 रुपए, तेलंगाना में 7800 रुपए, छत्तीसगढ़ में 4500 रुपए, मध्यप्रदेश में 5750 रुपए और पंजाब में 6300 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। आंगनवाड़ी हेल्पर की बात करें तो हरियाणा में 6781 रुपए ,छत्तीसगढ़ में 3250 रुपए, मध्यप्रदेश में 5000 रुपए, पश्चिम बंगाल में 4800 रुपए और पंजाब में 5000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। इन आंकड़ों से जाहिर हो रहा है कि हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्परों को अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा वेतन और सुविधाएं मिल रही हैं।

सेवानिवृति पर अनुदान देने की योजना

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पिछले दिनों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृति पर एक लाख रुपए तथा आंगनवाड़ी हेल्परों को 50 हजार रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को दुर्घटना होने उपरांत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। वहीं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 10 वर्ष से अधिक सेवा का अनुभव रखती है उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वरिष्ठता एवं लिखित परीक्षा के आधार पर पॉलिसी के अनुसार पदोन्नत करने की घोषणा की गई है। श्रीमती ढांडा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा किसी आंगनवाड़ी वर्कर की छंटनी नहीं की जा रही है। आईसीडीएस के निजीकरण की भी कोई योजना नहीं है।

हरियाणा में निवेश करेगा संयुक्त अरब अमीरात

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के निवेशकों को हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा निवेशकों के लिए कई कदम उठाए गए हैं और राज्य में कई तरह की विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

चंडीगढ़ में आयोजित भारतीय व्यापार भागीदार कार्यं म के साथ एक समझौता ज्ञापन और मैजेस्टिक इन्वेस्टमेंट, शीपेस, विजापास्पो, जगेरोस के कार्यं म में हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज व यूनाइटेड अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री और शासक परिवार के सदस्य शेख मजीद राशिद अल मुअल्ला और उनकी कोर टीम के सदस्य मौजूद रहे।

250 से अधिक फॉर्च्यून कंपनिया

हरियाणा भारत के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक है और राज्य को भारत का एक औद्योगिक पावरहाउस माना जाता है, जिसमें 250 से अधिक फॉर्च्यून कंपनियां हरियाणा में स्थित हैं। देश के 1.3 प्रतिशत क्षेत्र को कवर करने वाले हरियाणा ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3.94 प्रतिशत का योगदान दिया है। 2.54 करोड़ की कुल जनसंख्या (2011 की जनगणना) के साथ राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2,39,535 रुपए है, जोकि भारत की प्रति व्यक्ति आय से दोगुनी है। जीएसवीए में उद्योग क्षेत्र का योगदान 30.2 प्रतिशत है और राज्य में एफडीआई 1.7 बिलियन अमरीकी डालर (अप्रैल 2020-मार्च 2021) है जो इसे देश में छठा सबसे बड़ा एफडीआई बनाता है।

कारोबार की अधिक संभावनाएं

राज्य का लगभग 60 प्रतिशत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मजबूत कनेक्टिविटी के अंतर्गत आता है। फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, हिसार, सोनीपत, मानेसर, गुरुग्राम जैसे प्रमुख जिलों को कवर करने वाले फ्रेट कॉरिडोर-दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) के साथ इसका भौगोलिक संगम और अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी) के अंतर्गत आने वाला एक बड़ा क्षेत्र है। राज्य में 5 घरेलू हवाई अड्डे हैं, जैसे हिसार, भिवानी, करनाल, नारनौल और पिंजौर तथा 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों-चंडीगढ़ और नई दिल्ली से निकटता भी है। हरियाणा में 9 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), 3 कंटेनर फ्रेट स्टेशन और 8 निजी फ्रेट टर्मिनल हैं जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक हैं।

भारत-यूएई के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध

भारत-यूएई व्यापार का मूल्य लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर (फरवरी 2020) है। भारत में यूनाइटेड अरब अमीरात का निवेश लगभग 13-14 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है; यह भारत के लिए 10वां सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक भी है।

भारत में यूएई का निवेश मुख्य रूप से पांच क्षेत्रों सेवा क्षेत्र, समुद्री परिवहन, बिजली, निर्माण गतिविधियां और निर्माण विकास (टाउनशिप, हाउसिंग, बिल्ट-अप इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण-विकास परियोजनाएं) में है। एचसीएल इंफोसिस्टम्स, विप्रो, टाटा, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, डेन्यूब, एलएंडटी, शोभा ग्रुप, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसर ग्रुप सहित कई प्रमुख भारतीय कंपनियों के कार्यालय यूएई में हैं।

-संवाद ब्यूरो

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
संपादकीय टीम : संगीता शर्मा, सुरेंद्र मलिक
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

वायु प्रदूषण को देखते हुए गुरुग्राम में पिछले वर्ष अगस्त में प्रोजेक्ट 'परिवर्तन' लांच किया गया था, जिसमें डीजल या पैट्रोल ऑटो को बदलकर 'ई-ऑटो' खरीदने वाले ऑटो चालक को इनसेंटिव दिया जा रहा है।

दिव्यांगों की सहायता के लिए सरकार ने दिव्यांगता उन्मूलन तथा दिव्यांग पुनर्वास योजनाएं शुरू की हैं। इसमें पोलियो ड्राप पिलाने, चिकित्सालय खोलने, चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं।

मेरा परिवार, नशा मुक्त परिवार

दूध दही का खाणा, नशामुक्त हरियाणा

मनोज प्रभाकर

नशा समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बना है। हर कोई जानता है कि नशा हानि के अलावा कुछ नहीं देता, बावजूद इसके इसका कारोबार फलने फूलने लगता है जो देखते देखते हम सबके लिए चुनौती बन जाता है। असल में नशे की लत बेहद बुरी है। जो व्यक्ति नशा करने लग जाता है वह परिवार समेत बर्बादी की राह पकड़ लेता है। वह नशे के लिए सबकुछ दांव पर लगाने लगता है। कुछ ही समय पश्चात नशा करने वाला नशे की और पीड़ित परिवार गरीबी की दलदल में फंस जाता है। हालात नहीं सुधरते हैं तो नशा करने वाला व्यक्ति अपने पीछे अनेक परेशानियां छोड़कर दुनिया से रुख़्सत हो जाता है। इस संकट से जूझते काफी परिवार हैं, जो बदनामी के भय से खुलकर बोल नहीं पाते।

राज्य सरकार ने इस संकट के प्रति गंभीर चिंता जताई है। सरकार ने इससे निपटने के लिए व्यापक दृष्टिकोण के तहत अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत न केवल पीड़ितों को नशे से उबारा जाएगा बल्कि प्रदेश को नशामुक्त किया जाएगा। मनोहर सरकार ने संकल्प लिया है कि दूध दही वाले हरियाणा प्रदेश से नशे को बिलकुल समाप्त किया जाएगा। नशे के लिए यहां कोई स्थान न हो। गृहमंत्री अनिल विज ने ऐलान कर दिया है कि नशे का कारोबार करने वाले लोग या तो यह धंधा छोड़ दें या हरियाणा छोड़कर चले जाएं। इसमें माफी की कोई गुंजाइश नहीं है।

समाज की इस बुराई को समाप्त करने के लिए लोगों का जागरूक होना अनिवार्य है। सबके सहयोग से ही इस बुराई पर विजय पाई जा सकती है। खासकर युवाओं को इसके लिए आगे आकर एक मिशन के तौर पर कार्य करना होगा।

प्रदेश में नशे के कारोबारियों का रैकेट तोड़ने के लिए कानून की सख्ती से अनुपालना की जा रही है। इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है, जिसके माध्यम से नशा कारोबारियों व बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों को पकड़ा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से 61 नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं, जिनमें पिछले वर्ष 25 हजार युवाओं को नशे की बीमारी से मुक्ति दिलाई गई।

केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर देशभर में घूम-घूमकर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे हैं और लोगों को नशामुक्ति का संकल्प दिला रहे हैं। विगत दिनों उन्होंने भी हरियाणा का दौरा किया और युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया।

युवाओं को चाहिए कि वे अपने घरों के बाहर 'मेरा परिवार नशा मुक्त परिवार' लिखें। बता दें आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर 75 लाख लोगों को नशा न करने का संकल्प दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इतने लोग नशे से मुक्त होंगे तो उनके परिवारों के लिए 'आजादी के अमृत महोत्सव' की सार्थकता साबित हो जाएगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य से नशा खत्म के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गठित किया गया है। उन्होंने कहा कि नशा हर तरह से हानि पहुंचाता है। इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए हम सभी को सतत प्रयास करने होंगे। विद्यार्थियों को संकल्प लेना होगा कि 'वे जीवन में कभी भी नशा नहीं करेंगे।'

धुम्रपान निषेध संबंधी हिदायतें

रेलवे, बस अड्डा, सिनेमा हॉल, शैक्षणिक संस्थान, होटल आदि सार्वजनिक स्थानों की सीमा के भीतर धूम्रपान की सख्त मनाही है। सार्वजनिक स्थान पर 'धूमपान मुक्त क्षेत्र' के चेतावनी बोर्ड लगाना, मुख्य द्वार पर नोडल अफसर का नाम, फोन नंबर लिखा होना अनिवार्य हैं। सार्वजनिक स्थान पर ऐश-ट्रे, लाइटर, माचिस इत्यादि धूम्रपान के प्रमाण पाए जाने पर तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से उल्लंघन करने पर दो वर्ष के कारावास का प्रावधान है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पम्फलेट, स्टिकर, होर्डिंग इत्यादि द्वारा विज्ञापन करने पर जुर्माना व पुनः उल्लघंन करने पर 5 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। तम्बाकू उत्पादों के पैकेट पर दोनों तरफ 85 प्रतिशत चित्र सहित स्वास्थ्य चेतावनी प्रिंट होना आवश्यक है। ऐसा न होने पर 5000 रुपए तक जुर्माना या 2 से 5 वर्ष तक की कैद है।

फरीदाबाद तंबाकू मुक्त बनने की ओर अग्रसर

फरीदाबाद डीसी जितेन्द्र यादव ने कहा कि जिला में धूम्रपान निषेध अधिनियम (कोटपा) के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने और सिगरेट की खुली बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध है। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कोटपा के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने अथवा नियमों का उल्लंघन करने पर प्रति उल्लंघन 200 रुपए तक जुर्माना या कैद की सजा का प्रावधान है।

नोडल अधिकारी डॉ. नरिन्दर कौर ने बताया कि कि नागरिक व बीके अस्पताल में तंबाकू निषेध केंद्र बनाए गए हैं। जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए यहां काउंसलर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऐसे लोगों के लिए जल्द ही वर्निसिलिन जैसी दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

नशे के खिलाफ चलेगा व्यापक अभियान

नशे से संबंधित सभी पहलुओं पर अध्ययन के बाद हरियाणा राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो द्वारा एक विस्तृत स्टेट एक्शन प्लान बनाया गया है। ब्यूरो द्वारा 'हॉक' सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप 'प्रयास' के माध्यम से नशे के तस्करों, तस्करी में संलिप्त लोगों का डाटा बैंक तैयार किया जा रहा है, जिससे किसी संबंधित तस्कर के बारे में कोई भी सूचना तुरन्त प्राप्त कर बिना किसी देरी के कार्रवाई की जा सके।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पूरे राज्य में नशीले पदार्थों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए फॉरवर्ड, बैकवर्ड लिंकेज मैकेनिज्म स्थापित किया गया है। पिछले एक साल में हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और हरियाणा पुलिस ने 2,746 अभियोग दर्ज किये हैं और 3,975 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 29.13 किलो हेरोइन, 157.25 किलो चरस, 11,368 किलो गांजा, 356.19 किलो अफीम, 8550 किलो चूरापोस्त और 13 लाख 64 हजार 121 नशीली गोलियां, सिरप इत्यादि जब्त किया है।

तस्करी छोड़ दो, या हरियाणा छोड़ो दो

गृह मंत्री अनिल विज ने नशा तस्करों को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो उन्हें नशा तस्करी बंद करनी होगी, नहीं तो हरियाणा छोड़ना होगा। ब्यूरो द्वारा नशा पीड़ितों की सहायता और नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों की सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर 90508-91508 जारी किया गया है, जो 24 घण्टे खुला रहता है। इस नम्बर पर कोई भी व्यक्ति नशे से संबंधित सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाया जाएगा और इसके लिए नारकोटिक्स विभाग के अलावा अन्य पूरे पुलिस विभाग को ड्रग्स के अलावा जुआ, शराब, तस्करी, अवैध हथियारों में शामिल लोगों पर नकेल कसने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि नशे का कारोबार करने वालों की संपत्ति कुर्क करने की योजना भी बनाई जा रही है।

प्रदेशभर की आईटीआई में अभी तक 76 प्रकार के इंजीनियरिंग व नॉन इंजीनियरिंग कोर्स करवाए जा रहे हैं। जल्द ही 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' के तहत आईटीआई में शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू होने जा रहे हैं।

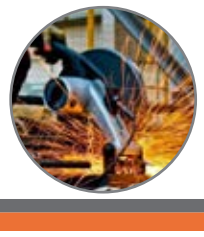

हरियाणा में 250 से अधिक फॉर्च्यून कंपनियां में स्थित हैं। देश के 1.3 प्रतिशत क्षेत्र को कवर करने वाले हरियाणा ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3.94 प्रतिशत का योगदान दिया है।

ड्रोन के लिए लाइसेंस, मिलेगी सब्सिडी

संगीता शर्मा

स्कूटर व कार चलाने के लिए लाइसेंस के बारे में तो आप सब ने अवश्य सुना होगा, लेकिन 'कृषि विमान' को प्रयोग करने के लिए सरकार की ओर से लाइसेंस जारी किया जाएगा। 'ड्रोन' का प्रयोग करना सेंसेटिव मामले से जुड़ा होता है, इसलिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। हरियाणा सरकार की ओर से अभी इसके लिए नियम-शर्तें बनायी जा रही हैं। इसके साथ ही ड्रोन खरीद से मिलने वाली सब्सिडी से भी किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी।

ड्रोन का उपयोग किसानों के लिए खेती में नया आयाम स्थापित करेगा। केंद्रीय बजट में भी कृषि में कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव करने के लिए 'कृषि विमान' के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) के सहयोग से गुरुग्राम के एफएमडीआई ट्रेनिंग सेंटर में 9 फरवरी से 14 फरवरी तक 'कृषि विमान- ट्रेनिंग इनेशेटिव ऑन ड्रोन स्प्रेइंग' आयोजित की गई। इसमें 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, इंजीनियर्स, किसान उत्पादक संगठन के सदस्यों व प्रगतिशील शामिल रहे।

ड्रोन की बारीकियां सीखीं

संयुक्त निदेशक (एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग), हरियाणा के इंजीनियर जे.एस नैन ने कहा कि कृषि में ड्रोन का उपयोग आधुनिक खेती के लिए मिसाल साबित होगा। इससे न केवल किसानों की लागत कम होगी, बल्कि फसलों के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। कृषि विमान चंद मिनटों की उड़ान 2.5 एकड़ के क्षेत्र में उर्वरक का छिड़काव कर सकती है। यह किसानों को आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करके और 2025 तक आय को दोगुना करने और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की ओर बेहतरीन कदम है।

खेती में नया प्रयोग

सहायक कृषि अभियंता, नूह इंजीनियर विजय कुमार ने बताया कि एक ड्रोन की कीमत दस लाख रुपए है। कृषि में आगे का भविष्य ड्रोन से खेती का ही है, इससे समय, लागत में बचत होगी और किसानों को अधिक मुनाफ़ा होगा। रेवाड़ी के पावटी किसान उत्पादक संगठन के निदेशक व प्रगतिशील किसान सूर्यदेव ने बताया कि ड्रोन से खेती से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में बहुत कुछ सीखने का मिला और जिसे वह अपनी खेती में प्रयोग करेंगे। वह बताते है कि अधिक से अधिक किसान कृषि विमान खरीदना चाहते हैं, ताकि समय व लागत की बचत हो। सही ढंग से खेती करने से अधिक मुनाफ़ा कमा सकें। वह कहते हैं कि सरकार की ओर से जो कृषि विमान के लिए रियायतें दी जाएगी उससे किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी।

ड्रोन के फ़ायदे

- बेहतर फसल उत्पादन के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है। इससे सिंचाई योजना, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी, कीटनाशकों का छिड़काव में मदद मिल सकती है।
- खेती में ड्रोन के प्रयोग से 90-95 प्रतिशत पानी की बचत होगी।
- पहले 45-50 किलो यूरिया बैग का खेत में प्रयोग होने पर 200-250 लिटर पानी बर्बाद होता था, अब नैनो यूरिया में 500 एमएल बोतल में 10 लिटर पानी का प्रयोग होगा। इसका छिड़काव ड्रोन से किया जाएगा।
- पहले खेत में छिड़काव करने से 40 प्रतिशत छिड़काव ही पौधों तक पहुंचता था, अन्य छिड़काव ज़मीन व हवा से बर्बाद हो जाता है। अब ड्रोन से 40-70 प्रतिशत छिड़काव बचेगा। पौधे के हर भाग में छिड़काव संभव हो सकेगा।
- खेत में पेस्टीसाइड व केमिकल का किसानों के हाथ-पांव व शरीर के अन्य भाग में गिरने से स्वास्थ्य को नुक़सान होता है और अब ड्रोन के प्रयोग से समस्या हल होगी। खर्चे बचेंगे और लागत में कमी आएगी।

किसको कितनी मिलेगी सब्सिडी

ड्रोन खरीदने पर हरियाणा सरकार की ओर से किसान उत्पादक संगठन को 75 प्रतिशत, कस्टमर हायरिंग सेंटर को 50 प्रतिशत और व्यक्तिगत तौर से किसान को ड्रोन खरीदने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। इसकी कीमत दस लाख रुपए के करीब है। इफको व गो ग्रीन कंपनी ड्रोन तैयार कर रही है। ड्रोन का प्रयोग करने के लिए सरकार की ओर से लाइसेंस भी जारी किया जाएगा, जिसका अभी प्रोसेस चल रहा है।

पराली से होने लगा बिजली उत्पादन

रेवाड़ी जिला के गांव खुर्शीदनगर में पराली से बिजली का उत्पादन करने वाला देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट स्थापित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में स्थापित किया गया यह प्लांट प्रदूषण मुक्ति के साथ ही बिजली के उत्पादन का सराहनीय कदम है।

हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के माध्यम से निजी क्षेत्र की के-2 पॉवर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड ने रेवाड़ी के गांव खुर्शीदनगर में देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट स्थापित करते हुए रेवाड़ी जिला को अनुकरणीय बनाया है। खुर्शीदनगर में पराली से तैयार हो रही बिजली को प्लांट से बिसोहा 33 केवी सब स्टेशन में उपलब्ध कराया जा रहा है और सब स्टेशन से बिसोहा गांव में बिजली की नियमित आपूर्ति शुरू हो गई है।

इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के आगाज पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पराली प्रबंधन की दिशा में उठाए गए कदम को सराहनीय बताया है। पराली से बिजली उत्पादन की दिशा में उठाए गए इस कदम से अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी सहित बिजली वितरण निगम की पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच सामने आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पराली प्रबंधन को लेकर दिए गए सुझावों को अमल में लाने में रेवाड़ी जिला उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। ग्रीन एनर्जी प्लांट में बिना प्रदूषण के 24 घंटे में 600 क्विंटल पराली से 48 हजार यूनिट बिजली का उत्पादन शुरू किया गया है। बिजली के उत्पादन के साथ ही क्षेत्र के इस प्लांट में लगभग 150 लोगों को सीधे रोजगार भी मिल रहा है।

पंचकूला रिन्यूवल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से मान्यता प्राप्त यह पहला पूरी तरह से प्रदूषण रहित प्लांट है। इसमें 400 किलोवाट क्षमता के पांच इंजन हैं, जिनसे बिना प्रदूषण के पराली से बिजली की उत्पादन प्रक्रिया को शुरू किया गया है। दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के 33 केवी सब स्टेशन बिसोहा को दो मेगावाट बिजली प्रति घंटे प्रदान की जा रही है और उक्त उत्पादित बिजली वितरण प्रक्रिया का भुगतान सरकार के नियमानुसार किया जा रहा है।

पराली से चलने वाला यह प्लांट बॉयलर की बजाय बायोमैस गैस विधि से काम कर रहा है, जिसमें प्रदूषण की कोई आशंका नहीं है। पराली से चलने वाले पांचों इंजनों से तैयार होने वाली गैस से ही बिजली का उत्पादन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह स्थित लघु सचिवालय में नवनिर्मित दृश्यम कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। इस कंट्रोल रूम से जिले में आपराधिक गतिविधियों पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी।

सरकार ने डीबीटी सिस्टम लागू करके बिचौलियों को खत्म करने का काम किया है। अब फसल का मुआवज़ा, फसल सरकारी खरीद की भुगतान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती हैं।

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का संकल्प

बजट सत्र में पेश होगी गांव की बदलती तस्वीर

मनोज प्रभाकर

राज्य सरकार की ओर से वर्तमान बजट में ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। अढ़ाई करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी गांव में बसती है। कृषि प्रधान सूबे में गांवों की संख्या छह हजार दो सौ से ज्यादा है। वर्तमान राज्य सरकार ने गांवों को 'आत्मनिर्भर' बनाने की दिशा में अनेक पहलें की हैं। गांव खुशहाल होगा तो प्रदेश स्वतः समृद्ध होगा। ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। विकास कार्यों में कोई गड़बड़ न हो इसके लिए पूरा डाटा ऑनलाइन किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल का संकल्प है कि सरकार की ओर से जो बजट विकास के लिए जारी होता है उसका एक-एक पैसा ईमानदारी से संबंधित कार्य पर खर्च हो।

आधारभूत संरचना के लिए सड़क मार्ग, गलियां, पुल, राजकीय भवन के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, बिजली व अन्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए पंचायतों व स्थानीय निकायों के अधिकारों का विस्तार किया गया है। दस हजार व इससे अधिक आबादी वाले गावों में सीवरेज की व्यवस्था की जा रही है। कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार ने योजनाओं में कोई संकोच नहीं किया है, और न बजट में कोई कंजूसी बरती है।

प्रसन्न्ता की बात यह है कि बहुत सी जागरूक पंचायतों व मौज़िज ग्रामीणों ने अपनी मेहनत व लगन से गांवों में न केवल विकास कार्य कराए हैं बल्कि स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा है। इसके लिए उन्होंने संबंधित विभागों का मार्गदर्शन व सहयोग लिया तथा गांव स्तर पर आने वाले वैचारिक मतभेदों को भी मिल बैठकर दूर किया। सीवरेज व्यवस्था, गलियों की साफ सफाई, राजकीय सेवाओं की उपलब्धता व सामाजिक सौहार्द के मामले में अनेक गांव आदर्श गांव कहे जा सकते हैं। बहुत से गांव स्टार रेटिंग हासिल कर चुके हैं।

थोड़ा चिंता वाली बात यह है कि बहुत से गांवों में जागरूकता की कमी के चलते पर्याप्त विकास कार्य नहीं हो पाए तथा कुछेक गांवों में आपसी तालमेल की कमी के चलते भी विकास कार्य बाधित हुए। यहां प्रत्येक ग्रामीण को 'मेरा गांव मेरा अभिमान' की भावना से विकास में सहयोग देना होगा। सबके साथ से ही सबका विकास संभव हो पाएगा। वैचारिक रूप से सकारात्मक रहेंगे तो गांव भी खुशहाल होगा और गांव का नाम भी रोशन होगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए अधिकारी राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं को सही ढ़ंग से धरातल पर उतारें, इससे निश्चित रूप से गांवों की तस्वीर बदलेगी। उन्होंने कहा कि आज 2 तिहाई आबादी गांवों में बसती है। हमें उनकी आशाओं पर पूरा उतरना होगा।

ग्राम स्तर कमेटी करेंगे निगरानी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जब तक प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होते तब तक विकास कार्यों में अहम भूमिका निभाने के लिए ग्राम स्तरीय कमेटियां गठित की जाएंगी। इन कमेटियों के परामर्श से ही गांव में कार्य करवाए जाएंगे। इससे गांव में विकास कार्य भी प्रभावित नहीं होंगे और जन प्रतिनिधियों की मांगों की सुनवाई हो सकेगी। इसके साथ-साथ ग्राम सभा की बैठकें भी नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए अधिकारी व जन प्रतिनिधि मिलकर काम करें ताकि इसके बेहतर परिणाम आएं। एक-एक पैसा जनता के काम आना चाहिए।

ताकि दूर दराज तक पहुंचें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं

वर्तमान सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए प्रयासरत है। दूर-दराज के गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए जल्द ही एक नीति बनाई जाएगी ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ तरीके से उपलब्ध हो सकें।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने एक प्री बजट चर्चा में कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है ताकि प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकें।

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि वर्ष 2014 में स्वास्थ्य विभाग का बजट 1500 करोड़ था जो बढ़कर 6500 करोड़ रुपए को पार कर गया है। राज्य के चार जिलो में कैथलैब संचालित है तथा शेष जिलों में स्थापित करने की प्रि या जारी है। इसी प्रकार, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासांउड व आईसीयू की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा, वर्तमान राज्य सरकार ने हर जिले में मेडिकल कालेज खोलने का निर्णय लिया है जिसके तहत चार जिलों में मेडिकल कालेज हैं तथा तीन में निर्माणाधीन है तथा तीन जिलों में मेडिकल कालेज को खोलने की अनुमति मिल चुकी है।

पीजीआईएमएम, रोहतक में अनुसंधान के कार्य पर बल दिया जाएगा। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आवश्यतानुसार मैपिंग का कार्य भी किया जाएगा ताकि हरियाणा के किसी भी व्यक्ति को उपचार करवाने के लिए हरियाणा से बाहर न जाना पड़े।

नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद के. पॉल ने कहा कि स्वास्थ्य सैक्टर को बड़ी प्राथमिकता दी जानी चाहिए और भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य के बजट को राज्य सरकारों के लिए कुल बजट का 8 प्रतिशत निर्धारित करने का लक्ष्य दिया है ताकि लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। डॉ पॉल ने कहा कि हरियाणा का स्वास्थ्य बजट वर्तमान में कुल बजट का 5.1 प्रतिशत है, जोकि अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर है।

पर्यटन स्थल बनेंगे तालाब

हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। बहुत से तालाबों के पानी को उपचारित किया जा रहा है तथा कुछ तालाबों को मॉडल तालाब बनाए जाने की योजना है। मॉडल तालाब के लिए 11 बिंदुओं पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाएगा जिनमें तालाब में इनलेट और आउटलेट का आवश्यक होना, ओवरफलोइंग का उचित समाधान करना, तालाब में पानी की न्यूनतम गहराई 8 फुट बनाए रखना, तालाब में समतल सतह, हरित पट्टी तथा जल ग्रहण क्षेत्र का होना, तालाब में डीपीडी तार की जाली का होना, तालाब की ग्रीन बेल्ट में प्राकृतिक पेड़-पौधे।

योजना के मुताबिक तालाब की जैव विविधता हो अर्थात मछली, कछुए, मेंढक, सांप, कमल के फूल की खेती, बत्तख, कैना तथा तालाब की प्रकृति के अनुसार जंगली घास व अन्य जड़ी-बूटी होनी चाहिए। वर्तमान में प्रदेश में कुल 16,350 तालाब हैं, जिनमें 15,910 तालाब ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और 440 तालाब शहरी क्षेत्रों में हैं तथा सभी तालाबों की जीआईएस मैपिंग कर पांड एटलस तैयार की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के 2606 तालाब प्रदूषित तथा ओवरफ्लोविंग हैं, 7963 प्रदूषित हैं परंतु ओवरफ्लोविंग नहीं हैं, 4413 तालाबों का पानी साफ है। प्रदूषित तालाबों के पानी को उपचारित करने के लिए कन्सट्रक्टिड वेटलैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा तथा हर तालाब के पानी की निकासी के सोलर पम्प प्रणाली लगाई जा रही है।

हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने 'जिंदल स्टेनलेस कंपनी' के साथ एक समझौता किया है। इससे विद्यार्थियों को तकनीकी में पारंगत होने का अवसर मिलेगा तथा उद्यमिता एवं स्वरोज़गार के रास्ते खुलेंगे।

हरियाणा सरकार नैचुरल फोरेस्ट्री और ग्रीनरी को संतुलित ढंग से विकसित कर रही है। प्रदेश में इस कार्य के लिए 770 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है ।

सशक्त महिलाएं, समृद्ध समाज

संगीता शर्मा

महिलाएं अब घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं हैं। वह आत्मनिर्भर बनकर अपने अधिकार व कर्त्तव्य के प्रति ज़ागरूक हो गई हैं। अपने हक व अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाती हैं। हरियाणा का महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए उनके साथ कदमताल मिला रहा है। 8 मार्च को 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' के अवसर पर हरियाणा सरकार द्वारा लड़कियों व महिलाओं के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं ताकि महिलाएं इन योजनाओं का भरपूर फ़ायदा उठा सकें।

राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और आवास देने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही है। महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सकें। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं', 'सुकन्या समृद्धि योजना', 'किशोर बालिकाओं के पुरस्कार' जैसे अनेक योजनाओं से हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार हुआ है।

कमलेश ढांडा, महिला एवं बाल विकास मंत्री, हरियाणा

हरियाणा राज्य महिला आयोग

हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम 2012 को पास करके उसे वैधानिक दर्ज़ा प्रदान किया गया है। जिसके अंतर्गत आयोग को महिलाओं से संबंधित मामलों में समन जारी करने, उपस्थित होने के लिए बाध्य करने, कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करवाने, शपथ-पत्र पर साक्ष्य मंगवाने, गवाहों एवं दस्तावेज़ों की जांच करने के उद्देश्य से दिशा-निर्देश देने जैसे सिविल कोर्ट के सभी अधिकार दिये गये है। वर्ष 2021-22 में आयोग को लगभग 717 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से लगभग 419 शिकायतों का निपटान किया गया। वर्ष 2021-22 के बजट में आयोग के लिए 11,000 लाख रुपए की राशि का प्रावधान रखा गया है।

राहत व पुनर्वास योजना

राज्य सरकार द्वारा तेज़ाब से पीड़ित महिलाओं के लिए राहत व पुनर्वास योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत तेज़ाब से पीड़ित महिलाओं को जो हरियाणा के निवासी है या हरियाणा में तेज़ाब से पीड़ित हुई हैं को सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत अब तक 16 तेज़ाब से पीड़ित महिलाओं व एक बच्चे को लाभान्वित किया गया है। योजना के तहत वर्ष 2021-22 के बजट में 30 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर 21 संरक्षण-सह-बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किए गए है, जिनके कार्यालय महिला पुलिस थाने में स्थापित किए गए हैं। पीड़िता को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड, जिला रैड क्रास समितियों, जिला बाल कल्याण परिषदों आदि 30 सेवा-प्रदाताओं का चयन किया जा चुका है।

विधवा एंव बेसहारा गृह

विभाग द्वारा विधवा एंव बेसहारा महिलाओं को आवास तथा रख-रखाव व ट्रेनिंग के लिए वर्तमान में महिला आश्रम करनाल तथा रोहतक में चलाए जा रहे हैं, जिनमें महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। वर्तमान में 75 परिवारों के साथ 51 निराश्रित सदस्य इन गृहों में रह रहे हैं।

हरियाणा उत्तर रक्षा गृह कन्या, करनाल

हरियाणा उत्तर रक्षा गृह कन्या (नारी निकेतन) तथा जिला परामर्श समिति के संचालन हेतू संशोधित हिदायतें तैयार की गई है। इसका उद्देश्य लड़कियों/महिलाओं जिनका कोई साधन न हो, को संस्थागत देखभाल, सरंक्षण, सामाजिक सुरक्षा, रख-रखाव, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। संवासियों को निःशुल्क कपड़े, भोजन, आवास, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता

महिला हैल्पलाईन-181

महिला हैल्पलाईन 3 दिसंबर, 2018 से कार्यशील है। महिला हैल्पलाईन, पीड़ित महिलाओं को 2437 विभिन्न सरकारी एजेंसियां जैसे वन स्टॉप सेंटर, संरक्षण-सह-निषेध अधिकारी, पुलिस और अस्पताल आदि के साथ समन्वय बनाते हुये तत्काल सेवाएं प्रदान करती है। 1 अप्रैल 2021 से नवंबर, 2021 तक विभिन्न जिलों से हैल्पलाईन पर कुल 38,875 कॉल प्राप्त हुई थी जिनमें से महिलाओं से संबंधित 6,124 प्रभावी कॉल थी।

- हरियाणा की लड़कियों व महिलाओं के विकास व उन्नति के लिये 'हरियाणा कन्या कोष' गठित किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस कोष के अंतर्गत 69.88 लाख रुपए की राशि जमा हो चुकी है।
- 'सकुन्या समृद्धि योजना' के अंतर्गत बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक खाता 1,000 की राशि से खाता खोला जा सकता है तथा निवेश के लिये अधिकतम राशि 1,50,000 रुपए वित्त वर्ष के दौरान है। इस योजना के तहत अब तक डाकघरों में 6,11,695 खाते खुलवाये जा चुके हैं।
- हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से एक छत के नीचे सभी सुविधाएं जैसे कि चिकित्सा सुविधा, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मानसिक एवं सामाजिक काउंसलिंग, अस्थाई आवासीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 'वन स्टॉप केंद्र' के सभी जिलों में स्थापना कर दी गई है।
- 'महिला एवं किशोरी सम्मान योजना' का उद्देश्य बी.पी.एल. परिवार की 10-45 वर्ष की किशोरियों एवं महिलाओं को मुफ़्त सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना है। युवतियों को आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से सेनेटरी पैड प्रदान किए जाते हैं।

पट्टी कल्याणा के दंगल में तैयार होते पहलवान

भारत-पाक विभाजन के बाद जिले पानीपत के गांव पट्टी कल्याणा में लाहौर से आये मलखान सिंह द्वारा प्रारंभ किए गए दंगल में कुश्ती के अनेक पहवान तैयार हो रहे हैं। आस-पास के एक दर्जन से ज्यादा गांव के लड़के व लड़कियां राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का जोरदार प्रदर्शन कर चुके हैं। पहलवान पिंकी राठी व नेहा सब जूनियर में बेहतर प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जीत का परचम लहरा चुकी हैं। ग्रामीण विक्की ने बताया की यहां की कुश्ती के पीछे इतिहास रहा है। किसी ज़माने में पहलवान मलखान सिंह द्वारा शुरू की गई कुश्ती अब नए आयाम की ओर है।

खेल के प्रति समर्पित यह गांव इस कदर बुलंदियों को छू रहा है कि 50 के करीब खिलाड़ी खेलों के बलबूते विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी कर रहे हैं। गांव की कोमल पांचाल सब जूनियर की खिलाड़ी हैं व दस जमा दो कक्षा की छात्रा है। कोमल ने बताया कि उनका लक्ष्य बाहर जाकर मैडल जीतने का है। मोनी छोकर स्पोर्ट्स में

बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं वो जूनियर वर्ग की खिलाड़ी हैं। वह कुश्ती के बलबूते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गांव का नाम रोशन करना चाहती है। नेहा शर्मा जूनियर वर्ग की खिलाड़ी है व अपने दावं पेच से अपनी से ताकतवर खिलाड़ी को भी मात देने का दमखम रखती है।

पट्टी कल्याणा के इन खिलाड़ियों को खेल के बलबूते सरकारी नौकरी मिली है इनमें संदीप वायु सेना में, नवीन रेलवे में, अमित, जयवीर, अनिल, अंकित, मनदीप और मोहित भारतीय सेना में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

कोच कृष्ण ने बताया कि 30 से ज्यादा बच्चे अभ्यास कर रहे हैं। ज्यादातर जूनियर वर्ग के बच्चे है जो आने वाले समय में बेहतरीन स्थिति में पहुंच जायेंगे। कोच विक्की ने बताया कि उनके पास 70 के क़रीब पहलवान प्रशिक्षण ले रहे हैं जिनमें 30 लड़कियां और 40 लड़के हैं। ज्यादातर खिलाड़ी अपने-अपने वजन के सुल्तान हैं। जिस प्रकार से खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं उसे देख कर लगता है वो मंजिल को अवश्य हासिल करेंगे। कोच विनोद के पास 15 के करीब बच्चे कुश्ती का नियमित अभ्यास करते हैं जिनमें 10 लड़कियां हैं। मेट व मिट्टी पर अभ्यास करने वाले इन खिलाड़ियों में कुश्ती के प्रति जज्बा व जोश साफ दिखाई पड़ता है।

-सुरेंद्र सिंह मलिक

आगामी एक वर्ष के लिए पांचवीं व आठवीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित किया गया है। इस वर्ष हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा इन परीक्षाओं को नहीं लिया जाएगा।

गुरुग्राम का श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नए मॉडल पर बनाया जाएगा, जिसमें कम खर्चे पर गुणवत्ता की हैल्थकेयर सुविधा उपलब्ध होंगी।

सुशासन के सहयोगी

सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे और हर परिवार आत्मनिर्भर हो इसके लिए हरियाणा सरकार नित नई योजनाओं पर कार्य कर रही है। योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है तथा उनकी समय समय पर समीक्षा की जा रही है। व्यवस्था में कोई कमी न हो तथा सब कार्यों में पारदर्शिता रहे इसके लिए जिला स्तर पर सुशासन सहयोगियों की मदद ली जा रही है। सहयोगियों ने डिजिटलाइजेशन के जरिए जो कदमताल मिलाए हैं उनके सुखद परिणाम आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का शुरु से प्रयास रहा है कि प्रदेश के लोगों का जीवन सहज व सरल हो। किसी से कोई भेदभाव न हो तथा एक समान विकास हो।

इस दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री ने सीएमजीजीए-2016 यानी मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम चलाया था जिसके सार्थक परिणाम मिल रहे हैं। अशोका विश्वविद्यालय को इस कार्यक्रम में रणनीतिक भागीदार के रूप में शामिल किया गया। ऑन-ग्राउंड डेटा और नागरिकों से प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के लिए जिला प्रशासन के साथ काम करने के लिए उत्साही युवा पेशेवरों को आगे लाया गया ताकि वे प्रमुख मुद्दों पर नवाचार ला सकें और विभिन्न कार्यों में उपायुक्तों का सहयोग कर सकें।

प्रशासनिक बेड़े में प्रति वर्ष 25 उत्साही एवं योग्य युवाओं की भर्ती की जाती है और उन्हें जिला मुख्यालयों पर रखा जाता है। ये सहयोगी मुख्यमंत्री कार्यालय के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करते हैं। राज्य सरकार के प्रमुख कार्यं मों के एक भाग को कार्य मॉड्यूल में परिवर्तित किया जाता है जिसे सहयोगी अपने जिलों में लागू करते हैं। इनके अलावा, सहयोगी अपने जिलों से संबंधित मुद्दों पर भी काम करते हैं और उनके लिए अभिनव समाधान प्रदान करते हैं।

कार्यं म के सफल पांच वर्ष

सीएमजीजीए कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक नीति, कानून, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आदि में सहयोगियों की विविधता और विभिन्न नवीन हस्तक्षेपों के माध्यम से बनाए गए सामूहिक प्रभाव के संदर्भ में विकसित हुआ है। सीएमजीजीए ने इन प्रक्रियाओं में से कुछ को हरियाणा में पिछले पांच वर्षों में सार्वजनिक सेवा वितरण, शिक्षा और महिला सुरक्षा सहित प्रमुख पहलों में उत्प्रेरित किया है, जबकि जमीनी स्तर पर कार्यं मों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया। यह कार्यक्रम हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री के सतत और अभिनव समाधानों के साथ राज्य को विकास की ओर ले जाने के दृष्टिकोण को संचालित करता है।

ई ऑफिस

ई आफिस सभी फाइलों को ऑनलाइन स्थानांतरित करने की एक प्रमुख पहल है। इसमें शासन प्रणाली में दूरगामी परिवर्तन लाने की क्षमता है। इससे समय व कागज की बचत होगी और कामकाज की गति भी बढ़ेगी। सहयोगियों ने जिला कार्यालय को समीक्षाओं की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली स्थापित की। जिला एवं राज्य स्तर पर विभागों में निष्ि य उपयोगकर्ताओं की पहचान करने का प्रावधान भी है।

प्रतिभाशाली युवा

कार्यं म के छठे समूह में 24 प्रतिभाशाली युवा पेशेवर शामिल हैं। एसोसिएट्स की विविध शैक्षिक पृष्ठभूमि है, जिसमें कानून और वाणिज्य से लेकर व्यावसायिक अध्ययन, अर्थशास्त्र, मानविकी और सार्वजनिक स्वास्थ्य शामिल हैं। मौजूदा दल में छह महिलाएं और 18 पुरुष हैं, जिनका औसत डेढ़ साल से अधिक का कार्य अनुभव है, जिनमें से कई जमीनी विकास क्षेत्र के संगठनों के साथ हैं।

सीएमजीजीए कार्यक्रम समस्या और समाधान पर काम करता है। अभिनव समाधान भी लागू करता है और जिला उपायुक्तों को शासन में श्रेष्ठ परिणाम लाने का समर्थन करता है। नागरिक सेवा वितरण, शिक्षा, कृषि और शासन में तकनीक पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

> प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुगम बनाने, अंतोद्य की भावना से हर राजकीय योजना का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचाने व नागरिकों का जीवन सहज व सरल बनाने के कार्य में सुशासन सहयोगियों की विशेष भूमिका रही है। जिला प्रशासन में इन सहयोगियों की भूमिका का और विस्तार किया जाएगा।
>
> **मनोहरलाल, मुख्यमंत्री हरियाणा**

मेरी फसल मेरा ब्योरा

'मेरी फसल मेरा ब्योरा' कृषि सूचना और खरीद प्र ियाओं को डिजिटलाइज़ करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि के अनुसार प्रदेश में उगाई जाने वाली सभी फसलों का डाटा एकत्रित करना है। इसका उपयोग किसानों के मुद्दों को हल करने एवं डेटा-समर्थित समाधान आवश्यक है।

सहयोगियों ने हरियाणा के सभी जिलों में उक्त पोर्टल पर 100 प्रतिशत पंजीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से काम किया है। उन्होंने कम पंजीकरण वाले गांवों की पहचान करने और योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ग्राम स्तर पर पंजीकरण शिविर आयोजित करने में जिला प्रशासन का समर्थन किया। हरियाणा के 480 से अधिक किसानों के साथ उनकी चुनौतियों की पहचान करने और माननीय मुख्यमंत्री को प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए ग्रुप

डिस्कशन भी आयोजित करवाया गया।

उल्लेखनीय है कि 2021-22 के रबी मौसम के लिए कुल भूमि का 64 प्रतिशत भाग पहले ही एमएफएमबी पर पंजीकृत किया जा चुका है। भविष्य में सहयोगी यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेंगे कि हरियाणा में सभी फसल/भूमि एमएमएफबी पोर्टल पर पंजीकृत हों और किसानों की शिकायतों का समय पर समाधान हो।

-संवाद ब्यूरो

सतत रोज़गार के अवसर प्रदान करेगा 'पदमा'

हरियाणा सरकार ने महत्वकांक्षी 'प्रोग्राम टू एक्सलरेट डेवलपमेंट फॉर एमएसएमई एडवांसमेंट (पदमा)' पहल की है। इसका उद्देश्य सतत रोजगार व उद्यमिता के अवसरों पर जोर देने के साथ-साथ संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाकर ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों पर केंद्रित विकासात्मक हस्तक्षेपों को डिजाइन और कार्यान्वित करना है।

कार्यक्रम के तहत स्थानीय रूप से प्रासंगिक उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा और राज्य के किसानों को उत्पादकों से लेकर प्रोसेसर बनने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

काबिलेजिक्र है कि औद्योगिक रूप से उन्नत जिलों में सकारात्मक विकास देखा गया है। यह प्रवृत्ति जारी रहने का अनुमान है और विकसित जिलों में विकास को बढ़ावा देने और औद्योगिक रूप से विकासशील जिलों में लक्षित क्लस्टर-आधारित हस्तक्षेप शुरू करने के लिए एक केंद्रित प्रयास की आवश्यकता है।

जो जिले अभी विकासशील हैं, उन्हें राज्य सरकार से विशेष प्रोत्साहन की आवश्यकता है, ताकि प्रदेशभर के युवाओं को आगे बढ़ने और समृद्ध होने तथा औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए एक समान स्थानीय अवसर प्रदान करना सुनिश्चित हो सके।

इस आशय के साथ राज्य के 22 जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों, मौजूदा एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र, हितधारकों के परामर्श, कच्चे माल की उपलब्धता, जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल और

विकास क्षमता के आधार पर सतत व लागत प्रभावी क्लस्टर बनाने के लिए एक उत्पाद की पहचान की गई है।

राज्य सरकार द्वारा चयनित उत्पाद हेतु जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक नया मिनी-औद्योगिक क्लस्टर विकसित किया जाएगा ताकि उत्पाद की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को मजबूत किया जा सके। यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक क्लस्टर कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) और बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस (बीडीएस) हब के साथ कई नए एमएसएमई को स्थापित करेगा।

कार्यं म के उद्देश्य

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सतत रोजगार व उद्यमिता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाकर ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों पर केंद्रित विकासात्मक हस्तक्षेपों को डिजाइन और कार्यान्वित करना है।

पदमा ब्लॉक स्तर पर समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास और एक मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा, राज्य के युवाओं को नए उद्यम स्थापित करने के लिए सशक्त बनाने और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने के अवसर भी प्रदान करेगा।

प्राइवेट सेक्टर में ऑटोरिक्शा से लेकर बड़े ट्रक चलाने के लिए कमर्शियल-ड्राइवरों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए राज्य सरकार कमर्शियल-ड्राइवरों को बेहतरीन प्रशिक्षण देने के लिए 'सेन्टर ऑफ एक्सेलेंस' खोलने पर विचार कर रही है।

सभी जिलों में सप्ताह भर के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 चलाया जाएगा। मिशन के लक्षित लाभार्थियों में 2 वर्ष से कम उम्र के गैर-टीकाकरण वाले बच्चे, गैर-टीकाकृत या आंशिक रूप से टीकाकरण वाली गर्भवती महिलाएं शामिल हैं।

सात नदियों का पवित्र जलस्रोतः सतकुंभा

हरियाणा का शायद कोई ही क्षेत्र ऐसा होगा जिसका संबंध किसी पौराणिक गाथा या महाभारत के साथ जुड़ा हुआ न हो। हरियाणा का सिंधुवन क्षेत्र तो कदम-कदम पर एक पुरातन किंवदंती को अपने में समेटे हुए है।

यमुनानगर जिले में स्थित कुछ तीर्थस्थल तो बहुत ही दर्शनीय हैं। जहां आदिबद्री नामक स्थान पर सरस्वती के उद्गम स्थल को मान्यता मिली है वहीं कपालमोचन सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक स्थल है जो हिंदू, मुस्लिम एवं सिखों के लिए समान रूप से महत्व रखता है। ऐसे ही स्थलों में से एक स्थल जो प्रशासनिक रूप से अभी तक गुमनामी के अंधेरे में है, परंतु जिसकी मान्यता दूर-दूर तक है, वह है- सतकुंभा। सतकुंभा यमुनानगर जिले के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में काला अंब के पास स्थित गांव असगरपुर से करीब चार-पांच किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है।

किंवदंती के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध के उपरांत पांडवों ने हस्तिनापुर में कई वर्ष तक राज्य किया। परंतु अंत में उन्होंने अभिमन्यु-पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य सौंपकर हिमालय-गमन का कार्यं म बनाया। परंतु हिमालय-गमन से पूर्व उनके मन में विचार आया कि उन्होंने महाभारत के युद्ध में जाने-अनजाने कितने ही वीरों का शोणित बहाया है; इतने पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? जब किसी महात्मा ने उन्हें बताया कि यदि वे फाल्गुन मास की अमावस्या को सबसे पहले सात नदियों के पानी में स्नान

कर लें तो किए गए पापों का फल शापित नहीं होगा। स्मरण रहे कि स्नान तुम सभी को एक साथ करना होगा और उस दिन उस एकत्रित जल में तुमसे पहले कोई भी स्नान न करे। महात्मा की बात सुनकर पांचों पांडव फाल्गुन मास की अमावस्या की प्रतीक्षा करने लगे। नियत दिन को सुबह जब वे सातों नदियों के पानी को एकत्रित करने चले तो वे जिस भी नदी पर जाते भगवान शंकर को अपने से पहले वहां पर पाते। शंकर जी उनसे पहले ही अपने कमंडल में जल इकट्ठा कर रहे थे। पांडवों के मन में विचार आया कि यदि अब की बार शंकर जी जल ले गए तो उन्हें एक वर्ष की प्रतीक्षा फिर से करनी होगी। परंतु पांडव एक वर्ष तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने शंकर जी से ही जल छीन लेने का विचार किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने शंकर जी का पीछा किया। पीछा करते-करते वे शिवालिक की इन्हीं पहाड़ियों में आ गए। जहां निकटवर्ती बस्ती का एक चरवाहा अपनी गऊएं और भैंसें चरा रहा था। शंकर जी ने पांडवों को भ्रमित करने के लिए एक भैंसे का रूप धर लिया। पांडवों की आंखों से शंकर जी ओझल हो गए थे। अचानक भीम की नजर एक भैंसे पर रखे कमंडल पर पड़ी। उसने सभी पांडवों को आश्वस्त किया कि हो न हो यही शंकर जी हैं। भीम संकरी घाटी के दोनों ओर अपने घुटने रखकर लेट गए । इस स्थान को गोडा डाहनी के नाम से जाना जाता है। भैंसे के रूप में भगवान शंकर भीम को देखकर पीछे की ओर दौड़ने लगे। सभी पांडवों ने एक पहाड़ी नाले में उन्हें पकड़ लिया परंतु कमंडल पाषाण पर गिरकर टूट गया। भगवान शंकर अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों को अपना आशीर्वाद दिया। जब पांडवों ने कहा कि उनका सारा श्रम बेकार चला गया, अब उन्हें एक वर्ष और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी तो शंकर जी ने कहा कि तुम्हें प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं, पाषाण पर गिरा यह सात धाराओं का जल कभी समाप्त नहीं होगा। तुम सब मिलकर स्नान करो और अपनी यात्रा आरंभ करो। पांडवों ने उस पानी में स्नान किया और हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। कहा जाता है कि तभी से उस पत्थर से ये सात धाराएं अविरल बहती चली आ रही हैं। मैदानी क्षेत्रों में भी जब तालाब, कुएं, नल सूख जाते हैं तब भी ये सात धाराएं निरंतर बहती रहती हैं। यद्यपि सतकुंभा नामक एक अन्य स्थल सोनीपत जिले में है और उस स्थल के साथ भी उपरोक्त कथा जोड़ी जाती है। परंतु शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित यह स्थल इस पौराणिक संदर्भ के अत्यंत करीब जान पड़ती है। यहां की भौगोलिक परिस्थितियां और पांडवों का हिमालय गमन तथा उस संदर्भ के सभी साक्ष्य यही गवाही देते हैं कि सतकुंभा नामक यह स्थल असली पौराणिक स्थल है।

बलदेव राज भारतीय

सुण छबीले बोल रसीले

साहित्यकार बणन की चाह

रमलू के बाबू, छोरी ईमला सिवासण होगी सै, ईब कितोड़ रिश्ते की बात कर ले।

छबीला बोल्या- ईमला की मां, तगाजा मत कर, बालक ईबै पढ़ैं सैं उननै पढ़ण दे। टेम आवैगा जिब सारे काम होज्यांगे।

रमलू के बाबू हाम गरीब आदमी सैं, न्यू कहा करैं अक गरीब आदमी नै आपणी छोरी के हाथ जितणा तावला हो, पीले कर देणे चाहिए।

- ये पराणी बात हो ली भागवान। ईब वो ज़माना गया। बालक ईब आपणे कैरियर पै ध्यान दे सैं। ब्याह शादी पै ना देते। म्हारी जातकी नै तो ईबै प्लस टू करी सै। बीए-एमए करण दे, कोय कोर्स करण दे। फेर सोचांगे रिश्ते के बारे में।

- मनैं तो डर लागे जा सै रमलू के बाबू, अक लोग के कहैंगे।

- भागवान पहली बात तो यो सै, अक लोग कुछ ना कहते, तूं आपो आप ना दिमाग नै फालतू चलाया कर। दूसरी बात यो सै अक जै कुछ कहते भी हों तो उन कान्या ध्यान नहीं देणा चाहिए। आपणे काम तैं काम राखो और बालकां कानी ध्यान देते रहो।

-रमलू के बाबू लोगां की तो देखी जा, पर लुगाइयां नै घणी बात आवैं सैं। कितो ए बैठकै धड़ी-धड़ी की बात मार दे सैं। फलाणी न्यूं-धकड़ी न्यूं।

- भागवान मनैं कही सै ना आपणा आपो

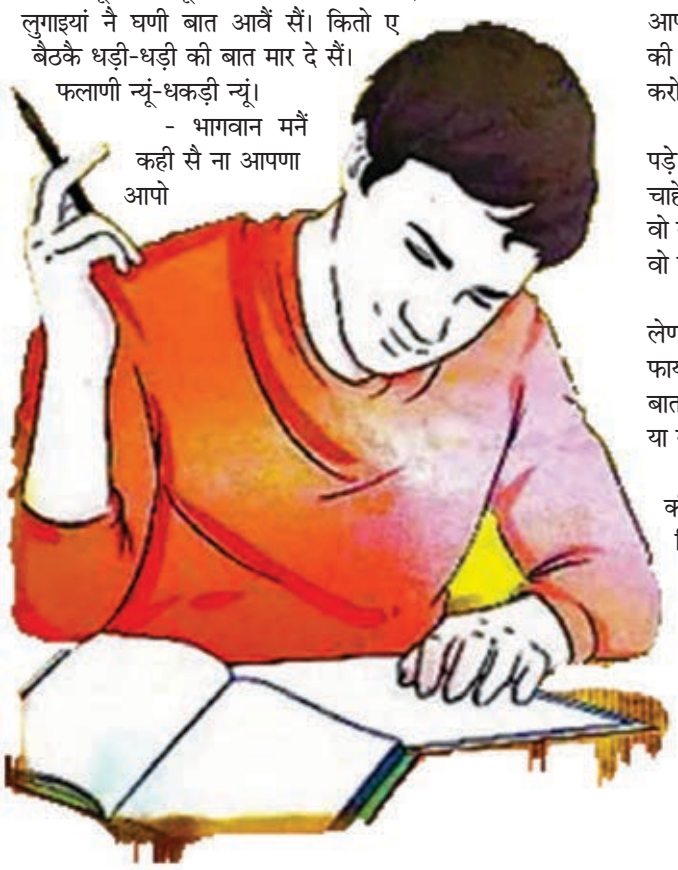

दिमाग ना चलाया कर। हाम सही सैं तो सब सही सैं। जो आदमी खुद गलत हो सै उसनै सब आपणे जिसे दिख्या करैं। न्यू कहा करैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। किसे के बारे में कुछ गलत नहीं कहणी चाहिए। ना सोचणी चाहिए। गलत सोचण तैं आगले का नुकसान तो के भरा ना हो, पर सोचण आले का जरुर होण लागज्या सै। किसे की पीछे तैं बुराई भी नहीं करणी चाहिए। जो गलत बोलता हो तो उसनै एक दो बार टोक दे। फेर भी ना मानैं तो उसतैं टल ले।

- रमलू के बाबू, बालकां के रिश्ते तो करणे सैं, आज नहीं तो कल।

- भागवान बालकां के रिश्ते करणा कोय बडी उपलब्धि कोन्या होती। उपलब्धि हो सै उनका कैरियर, उनकी नौकरी, रोजगार, आच्छा स्वास्थ्य, उनके आच्छे संस्कार, आच्छी उठ-बैठ। बालकां में ये चीज़ होंगी तो रिश्ते आपणे आप होज्यांगे। और उनमें ये चीज जिबै होंगी जिब हाम सही होंगे। म्हारा रहन सहन, बोल-चाल, ईमानदारी, घर ग्रहस्थी आदि।

रमलू की मां तूं देखै सै अक हाम बालकां तैं बराबर बात करते रह सैं। उनके साथ मित्रता वाला व्यवहार करैं सैं। गलत चाल चलन तैं सख्त परहेज करैं। अच्छी बात करैं और अच्छी राय दें। संस्कार आपणे आप बढ़िया बणगे। इसलिए उननै ईबै मन लगाकै पढ़ण दे। रिश्ते विश्ते की बात तो उनके साथ करणी भी नहीं चाहिए। बस कैरियर की बात करो।

भागवान देखती नहीं, देश की छोरी और छोरे पढ़ाई करण में जुटे पड़े सैं। और फेर न्यू कहा करैं- जिंदगी में संघर्ष तो करणा पड़े सै। चाहे पहल्या करल्यो या पाछै करल्यो। जो जवानी में संघर्ष कर लेगा वो साबत जिंदगी मौज़ करैगा। और जो ईब मटर गश्ती में दिन खो देगा वो सारी जिंदगी बिरान रहैगा।

- रमलू के बाबू, मनैं जिक्रा न्यू थोड़ा करया था अक मेरी क्लास लेण लागज्याइये। बालकां नै पढ़ा ले, मैं तो राजी सूं। पढ़ण लिखण का फायदा ए सै। पढ़ी लिखी जातकी नै सुसराड़ में कोय ऊंची आवाज में बात नहीं करता। सब हिचकैं सैं। देर सबेर वो खुद भी कामयाब होज या सै और पूरे परिवार नै कामयाबी की राह पै ल्या दे सै।

- मैं न्यूए तो कहूं सूं भागवान, और फेर हरियाणा सरकार नै छोरियां की शिक्षा खातिर खूब स्कीम चला राखी सैं। मुफ्त पढ़ाई हो सै। किताब, कापी, ड्रेस, वजीफा सब तरियां की सुविधा मिलै सै। कालेज में जाण खातिर ईब गाम तैं घणी दूर भी कोन्या जाणा। हर दस कोस के एरिये में कालेज सैं। बसां में फ्री पास की सुविधा सै। कुल मिलाकै सरकार की तरफ तैं कोय कमी कोन्या, बालकां में पढ़ण की लगन होणी चाहिए।

- ठीक सै रमलू के बाबू, ईसै बात पै तेरे खातिर दो घूंट चाय बणा ल्याऊं सूं।

- मनोज प्रभाकर

कुछ अगेती कुछ पछेती

हरियाणवी लोकगीतों में कृषि-गीतों की अनूठी झलक

हरियाणा सदियों से कृषि प्रधान प्रदेश रहा है। यहां के लोक गीतों में हरियाणवी लोक जीवन के ि याकलापों का अच्छा खासा वर्णन कृषि गीतों में मिलता है। कहीं कहीं आधुनिक कृषि यन्त्रों का भी प्रयोग किया जा रहा है। 'खेती खसमा सेती' वाली उक्ति की प्रधानता का समावेश भी रहता है। इन लोकगीतों में किसान के काम की बहुत सी बातें कही गई है। भूमि का महत्व बताते हुए कहा गया है-

मोठ, बाजरा, टिब्बा में राजी,
गेंहू राजी क्यारियां,
गोमाता सूखे में राजी और
भैंस राजी मारियां,
खेती करै सो उपरा करे,
ना तो घर मैं पडक़ै मरे,
ऊंचे-ऊंचे ड्योळे, डूंघे-डूंघे क्यार,
बरसै मालिक मूसलाधार,
डसमें ऊपजे उड़द ज्वार,
चैता चणा सौ गुणा जे डेहर आया हौ।
बीज फैला होना चाहिये,

इस संबंध का गीत-

तील छीदे जो साधने, मैंढक चाल ज्वार,
ऊंट पैर में बाजरा, धान पैर में चार,
छीदी-छीदी बन छटी, घोड़े हिंसे बहार,
हाथ पैनी बाजरा, मैंढक फुदक ज्वार,
और कीड़ नाल ढोये मोठ ग्वार।

फसल बोने का क्या-क्या समय है देखिए-

धी न राखिये लाड़ली,
बैशाख में बीजिए ईंख,
वे घर कदे ना बसे, जिन्ह ली पराई सीख,
साढ़ जो बोये बाजरा, सामण बोवै ज्वार,
मोठ जो बोवै भादवा, कभी ना आवै हार,
गेंहू खाणा चाहे था,
साढ़ में क्यूं ना गावै था,
खेती खसमां सेती,
कुछ अगेती कुछ पछेती,
नहीं तो रेती की रेती।

हाळी की रोटी कैसी और साग किसका ले जाया जाता है-

बाजरे की रोटी पोई रै हालिड़ा,
बथुए का रान्धा रै साग,
आठ बळधां का रै हालिड़ा,
नीरगा चार हालिड़ा की छाक,
बरसण लागी रै हालिड़ा बादळी।

ईंख की खेती में कठिन परिश्रम होने पर भी वह कष्ट प्रदान करने वाली मानी गई है।

बहोत सताई ईंखड़े तन्नै बहोत सताई रै,
बाळक छोडे रोवते रै तन्नै बहोत सताई रै,
डालड़ी मैं छोड्या पीसणा,
अर छोड्डी सै लागड़ गाय,
नगोड़े तै ईंखड़े तन्नै बहोत सताई रै।

डॉ. कैलाशचन्द शर्मा 'शंकी'

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com